बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 181

तेल का सामरिक सवाल

सऊदी अरब की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी अरामको के संयंत्र पर ड्रोन के जरिये हमले की अप्रत्याशित घटना ने भारत समेत समूची दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में यमन के हूती विद्रोहियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हमले के बाद अरामको ने अपने उत्पादन में आधी यानी प्रतिदिन करीब 60 लाख बैरल की कटौती करने की बात कही है जो वैश्विक तेल उत्पादन का पांच फीसदी है। इस घोषणा के बाद तेल की कीमतों में एक ही दिन में करीब 20 फीसदी तक उछाल आ गई जो कई वर्षों में आई सबसे बड़ी तेजी है। काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि सऊदी अरब किस तरह से तेल प्रसंस्करण को पटरी पर ले आता है और क्या हूती विद्रोहियों का समर्थन करने वाले ईरान और सऊदी अरब-अमेरिका गठजोड़ के बीच का तनाव काबू में रखा जा सकता है? हालांकि दूसरे बड़े तेल उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई कर सकते हैं और अमेरिका ने कहा भी है कि वह अपने सामरिक तेल भंडार के दरवाजे खोलेगा। भारत में डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट रही जो बाह्य क्षेत्र में अस्थिरता और मुद्रास्फीतिकारी दबावों के चलते गहराती चिंताओं को दर्शाता है।

अरामको संयंत्र पर हुए हमले ने भारत की दो सामरिक कमजोरियां उजागर की हैं। पहली, जरूरत का 80 फीसदी से भी अधिक तेल आयात करने वाला भारत अपने वृहद-आर्थिक स्थायित्व के लिए कम एवं स्थिर भाव वाले तेल पर निर्भर बना हुआ है। फिलहाल चालू खाता घाटे की स्थिति काबू में है जो घरेलू मोर्चे पर मांग में भारी कमी होने से है। लेकिन कच्चे तेल का भाव एक डॉलर प्रति बैरल चढ़ने पर भारत का आयात बिल 10,500 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। भारत ने वर्ष 2018-19 में तेल आयात पर 112 अरब डॉलर खर्च किए थे। भारत को कच्चे तेल एवं रसोई गैस का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब है।

अगर इसी समय अर्थव्यवस्था को कुछ और दबावों का सामना करना पड़ जाता है तो तेल के दाम बढ़ने से गहरा अस्थायित्व पैदा होगा। सरकार ने वर्ष 2014 के बाद तेल के भाव नीचे रहने के बावजूद इस सामरिक कमजोरी से निपटने की दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए हैं। इसका केवल एक वास्तविक समाधान ही है: उच्च एवं टिकाऊ निर्यात आय जो बाहरी खाते को लेकर भरोसा जगाएगी। लेकिन भारतीय निर्यात में कई वर्षों से सही मायने में नगण्य वृद्धि हुई है और गत अगस्त में यह एक साल पहले की तुलना में छह फीसदी लुढ़क गई। हमें समझना होगा कि निर्यात क्षेत्र में नई जान फूंकना न केवल वृद्धि बल्कि आर्थिक स्थिरता के लिहाज से भी अनिवार्य है।

दूसरी कमजोरी भारत के अपने तेलशोधन ढांचे से जुड़ी है। मसलन, गुजरात के जामनगर में स्थित निजी तेलशोधन इकाइयों पर मुंबई आतंकी हमले के बाद से ही सीमापार हमले का खतरा रहा है। इसी वजह से सरकार ने राष्ट्रीय महत्त्व के निजी प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। ऐसा खतरा सौर पार्कों जैसे अन्य निजी प्रतिष्ठानों को भी है। उन्हें ड्रोन हमलों से बचाकर रखना मुश्किल हो सकता है। मिसाइल-रोधी प्रतिरक्षा प्रणाली भी ड्रोन के आगे कारगर नहीं होती है क्योंकि वे रडार की पकड़ में आने से बच जाते हैं। दरअसल ड्रोन विमान तकनीक के मामले में कम नहीं होते हैं और उनकी खरीद एवं रखरखाव भी बहुत महंगा नहीं होता है। राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से इतर इलाकों में जिओ-फेंसिंग और ड्रोन पहचान प्रणालियों की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत होगी। नागरिक विमानन मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में ड्रोन नीति जारी की थी लेकिन अरामको संयंत्र पर हमले के बाद इस नीति की खामियों पर गौर करना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ड्रोन के कई उपयोगी एवं उत्पादक इस्तेमाल हैं और नियमों में बदलाव से तकनीकी नवाचार पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

अजय मोहंती

हॉन्ग कॉन्ग में उपद्रव का चीन पर प्रभाव

इसकी संभावना कम ही है कि हॉन्ग कॉन्ग दोबारा उसी दौर में वापस लौट सकेगा जैसा वह मौजूदा अशांति के पहले हुआ करता था। चीन के लिए इसकी अहमियत बता रहे हैं श्याम सरन

हॉन्ग कॉन्ग में राजनीतिक अशांति बदस्तूर जारी है और लगातार हिंसात्मक एवं चीन-विरोधी रुख व्याप्त है। बढ़ते विरोध को दबाने के लिए चीन की सेना के निर्मम एवं रक्तरंजित तरीकों का सहारा लेने की आशंका अधिक बलवती होती जा रही है। अमेरिकी दूतावास की तरफ कूच करते समय प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में अमेरिकी झंडे थाम रखे थे। वे अमेरिका से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगा रहे थे जो एक ऐसा उकसावा है जो नजरअंदाज किए जाने पर चीन एवं उसके राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए बड़ा आघात हो सकता है।

चीन के सामने अब समान रूप से अरुचिकर विकल्पों के बीच में से चुनने की चुनौती है। चीन की किताब में कम बुरा विकल्प हिंसात्मक दमन के बाद हॉन्ग कॉन्ग को शांघाई, ग्वांगतोंग या शेन्जेन की तरह पूरी तरह आत्मसात कर लेने का होगा। फिर हॉन्ग कॉन्ग का शासन चीनी संविधान के तहत बने कानूनों से संचालित होगा, न कि ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता की पृष्ठभूमि में विकसित अपने बेसिक लॉ के आधार पर। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया भर में तीसरे सबसे अहम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार के तौर पर उसका वजूद नहीं रह जाएगा। इस तरह वैश्विक बाजारों के साथ चीन के एकीकरण में हॉन्ग कॉन्ग की भूमिका खत्म हो जाएगी। इससे अमेरिका के साथ जारी व्यापार युद्ध और तीव्र हो जाएगा जो राजनीतिक तनाव बढ़ाने और एक वैश्विक वित्तीय स्थिति हासिल करने की चीन की आकांक्षा पर तगड़ा आघात करेगा।

जहां यह सच है कि हॉन्ग कॉन्ग अब पहले की तरह चीन के वृद्धि पथ में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा, वहीं चीन के लिए बाकी दुनिया के साथ व्यापार, बैंकिंग एवं वित्तीय संपर्क बढ़ाने में अहम मध्यवर्ती के तौर पर उसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी। पहले से सुस्थापित व्यापारिक चैनल होने, अपने परिष्कृत बैंकिंग ढांचे और अपने उच्च विकसित वित्तीय एवं प्रतिभूति बाजार होने से हॉन्ग कॉन्ग ने चीन को पहले से मौजूद एवं अंतर्संबंधों का सघन जाल मुहैया कराया था। इससे चीन अपनी अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण नियंत्रित एवं कम जोखिम के साथ कर पाया। यहां तक कि आज भी चीन आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा हॉन्ग कॉन्ग के जरिये ही पहुंचता है। इसके बैंकों ने चीन सरकार के स्वामित्व वाले एवं निजी कंपनियों के लिए जरूरी वित्त मुहैया कराने के साथ ही उनकी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के विस्तार के लिए आधार के तौर पर भी काम किया। हॉन्ग कॉन्ग के शेयर बाजार का पूंजीकरण पांच लाख डॉलर है जो चीन के 6.3 लाख करोड़ डॉलर पूंजीकरण से थोड़ा ही कम है। हॉन्ग कॉन्ग के बैंकों में विदेशी मुद्रा जमा 850 अरब डॉलर है जिसमें बड़ा हिस्सा मुख्य भूमि वाली कंपनियों का है। इस तटीय शहर में 1,300 से अधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पंजीकृत हैं जो चीन के अलावा समूचे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कारोबार कर रही हैं। हॉन्ग कॉन्ग के वित्तीय बाजार का इस्तेमाल चीन ने अपने वित्तीय क्षेत्र का चरणबद्ध ढंग से उदारीकरण और अपनी मुद्रा रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए किया। हॉन्ग कॉन्ग स्टॉक कनेक्ट के जरिये विदेशी संस्थागत निवेशक शांघाई और शेन्जेन के शेयर बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं। अब बॉन्ड कनेक्ट कार्यक्रम भी है जिसके जरिये वे चीन के 12 लाख करोड़ डॉलर के विशाल बॉन्ड बाजार में निवेश कर सकते हैं। हॉन्ग कॉन्ग रेनमिनबी का सबसे बड़ा अपतटीय बाजार भी है।

इससे भी बढ़कर औपचारिक तौर पर चीन का हिस्सा होते हुए भी हॉन्ग कॉन्ग की स्थिति अनूठी है। उसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक स्वायत्त सदस्य का दर्जा हासिल है और बाजार अर्थव्यवस्था के तौर पर खुद चीन को भी नहीं मिल पाने वाले विशेषाधिकारों से लैस है। अमेरिका-हॉन्ग कॉन्ग नीति अधिनियम 1992 के तहत हॉन्ग कॉन्ग की अमेरिकी बाजार में खुली पहुंच हासिल है। इससे चीन को हॉन्ग कॉन्ग के जरिये उच्च तकनीक वाले उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच मिल जाती है। चीन को होने वाले बौद्धिक संपदा लीकेज को लेकर अमेरिका एवं पश्चिमी देशों में बढ़ती चिंता के मद्देनजर हॉन्ग कॉन्ग एक पुनर्निर्यात केंद्र के तौर पर बेहद अहम हो जाता है। अगर अमेरिका इस विशेष कानून से अलग हो जाता है तो वह सीधे तौर पर हॉन्ग कॉन्ग और परोक्ष तौर पर चीन के लिए गहरा आघात होगा।

अगर हॉन्ग कॉन्ग में हो रहे प्रदर्शनों से व्यापक हिंसा के बगैर निपटा जाता है तो इसकी संभावना काफी कम है कि वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट सके। एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के तौर पर हॉन्ग कॉन्ग की कामयाबी में एक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित क्षेत्रीय व्यापार एवं लॉजिस्टिक केंद्र, एक स्थिर मुद्रा, एक परिष्कृत बैंकिंग प्रणाली और विकसित वित्तीय बाजार के तौर पर उसे हासिल भरोसे का बड़ा हाथ रहा है। इसकी न्यायिक प्रणाली को भी ऐंग्लो-सैक्सन वर्चस्व वाली विश्व अर्थव्यवस्था में विश्वसनीय माना जाता रहा है। यहां की सड़कों पर राजनीतिक अशांति एवं हिंसा का दौर जारी रहने से इस भरोसे में काफी कमी आई है। इसके बहाल हो पाने की संभावना नहीं है। चीन ने आर्थिक क्षति से बचने के लिए अभी तक दमन का रास्ता नहीं अपनाया है लेकिन अपनी संप्रभुता को खतरा और अपनी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचने का डर आगे शायद उसके हाथों को न बांध सके।

यह तंग श्याओ फिंग के 'एक देश, दो व्यवस्था' सिद्धांत के खात्मे का भी ऐलान करता है। तंग श्याओ फिंग ने हॉन्ग कॉन्ग, मकाओ और ताइवान जैसे पुराने विमुक्त क्षेत्रों का चीनी मुख्यभूमि से क्रमिक ढंग से एकीकरण करने के लिए एक नवाचारी तरीका निकाला था। ताइवान में चीन के साथ समाहित होने की राह में प्रतिरोध न सिर्फ बना रहेगा बल्कि समय के साथ बढ़ेगा। उस समय चीन में सैन्य साधनों का इस्तेमाल कर ताइवान के एकीकरण का दबाव बढ़ता जाएगा। ऐसे में हमें दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

भविष्य के लिए कैसा परिदृश्य है? वैश्विक वित्तीय बाजार के साथ एकीकरण और रेनमिनबी मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए चीन की कोशिश को गहरा आघात लगने की आशंका है। हॉन्ग कॉन्ग संकट से अमेरिका-चीन संबंध और बिगड़ेंगे जिससे उनके व्यापार युद्ध में समझौते की गुंजाइश भी कम होती जाएगी। भले ही अमेरिका एवं चीन को एक सूत्र में बांधने वाले सघन आर्थिक एवं व्यापारिक रिश्तों को समझ पाना मुश्किल होगा लेकिन आरंभिक वियुग्मन पहले से ही जारी है और अपनी आर्थिक लागत के बावजूद यह जोर पकड़ सकता है। चीन अपना ध्यान एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण पर लगा सकता है। चीन आरसेप जैसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौते और च्यांग मेई जैसी मुद्रा समाधान पहल के जरिये यह एकीकरण करना चाहेगा। च्यांग मेई को चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा आसियान के 10 सदस्य देशों के बीच रेनमिनबी मुद्रा क्षेत्र के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। विश्लेषक अभी से यह आशंका जताने लगे हैं कि आने वाले समय में दुनिया अमेरिकी डॉलर, यूरो और रेनमिनबी के प्रभाव वाले तीन क्षेत्रों में बंट जाएगी। यह बुनियादी तौर पर बहुध्रुवीय विश्व में प्रतिस्पर्द्धा एवं गठजोड़ के भविष्य में तीन भू-राजनीतिक क्षेत्र तैयार करेगा। सवाल है कि इस बदले परिदृश्य में भारत की जगह कहां होगी?

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)

अर्थशास्त्रियों की काबिलियत के मुताबिक मिले पद

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

वर्ष 2014 से मोदी सरकार की जिन तमाम कदमों के लिए आलोचना की जाती रही है उनमें से एक है अर्थशास्त्रियों में सरकार की रुचि न होना। परंतु अगर आप एक दशक पीछे जाएंगे, तब भी आपको यही दिक्कत नजर आएगी। न तो संप्रग सरकार ने और न ही मोदी सरकार ने अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति और काम को बहुत अधिक तवज्जो दी है। इस लिहाज से देखें तो दो किस्म की नियुक्तियां बहुत मायने रखती हैं, बशर्ते कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी इन्हें मायने रखने दें। एक पद है मुख्य आर्थिक सलाहकार का और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में आर्थिक मामलों के प्रभारी डिप्टी गवर्नर का। इन पदों पर बैठे लोगों को कुछ खास चीजों की चिंता करने के लिए वेतन मिलता है लेकिन अगर ये लोग गलत चीजों के बारे में चिंता करने लगें तो?

उदाहरण के लिए समाचार पत्रों की कार्यशैली पर बात करें तो यहां संपादन करने वालों को समाचार संकलन को लेकर चिंतित नहीं होने दिया जाता है और समाचार जुटाने वाले संपादन की चिंता नहीं करते। संपादकीय टीम का कोई भी सदस्य अगर समाचार संकलन करने वाले से सवाल जवाब करता है तो उसे तत्काल बता दिया जाता है कि यह गलत है। इसका उलटा भी उतना ही सही है।

बहरहाल, सरकार के सलाहकार पदों की बात करें तो वहां यह बुनियादी नियम लागू नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आईएएस अधिकारी काबिज हो चुके हैं। अगर सीवी (आत्म विवरण) बहुत प्रभावशाली है तो विशेषज्ञता कतई मायने ही नहीं रखते। मुझे नहीं पता कि हॉर्वर्ड की पीएचडी के अलावा अरविंद विरमानी की काबिलियत क्या थी लेकिन वह लंबे समय तक सरकार में काम करते रहे। उनके पूर्ववर्ती अशोक लाहिड़ी प्रशिक्षित अर्थमितिज्ञ थे। यानी उन्हें अर्थशास्त्र में आंकड़ों, आर्थिक मॉडलों, सांख्यिकी आदि का इस्तेमाल करने और नतीजे हासिल करने में महारत हासिल थी।

अर्थशास्त्री : कौशिक बसु मूलतया सिद्धांतकार थे। इतना ही नहीं वह सन 1993 से ही विदेश में रह रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी सरकार में काम भी नहीं किया था। स्वाभाविक सी बात है कि उनमें दो कमियां थीं। रघुराम राजन एक इंजीनियर थे जो भटकते हुए अर्थशास्त्र में आ गए। उनकी विशेषज्ञता वित्त में थी। अरविंद सुब्रमण्यन एक व्यापार अर्थशास्त्री थे। सरकार और देश की आर्थिक दिक्कतों को लेकर उनका रुख भी उन्हें सौंपे गए पद के अनुरूप नहीं था। इन अर्थशास्त्रियों, खासकर अंतिम तीन के बीच एक दशक बीतने के बाद हमें यह प्रश्न करने का अधिकार बनता है कि उनका योगदान क्या रहा? उनका सीवी तो इससे मजबूत हुआ लेकिन बदले में सरकार को क्या मिला?

वे भला योगदान कर भी कैसे सकते थे जबकि उनके पास जो जहाज थे, उसे सरकारी नीति के समुद्र को पार करना होता था। उपरोक्त तीनों अर्थशास्त्री अब अमेरिका में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने काम पर लौट गए हैं और अकादमिक अर्थशास्त्र में व्यस्त हो गए हैं।

हम उनकी बौद्धिकता को चाहे जितना भी मान दे दें, आईएएस अधिकारी उन्हें कतई गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि कई बार तो वे उन्हें परेशानी खड़ा करने वाला ही मानते रहे। यहां तक कि मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार भी वित्तीय क्षेत्र के व्यक्ति हैं। अंततः वे भी अकादमिक जगत में लौट जाएंगे। उनका सीवी भी मजबूत हो चुका होगा। ऐसे में मेरे पास एक सुझाव है: देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर आवेदन करने वालों के लिए कम से कम 10 वर्ष की शासकीय सेवा अनिवार्य हो। वर्ष 2004 तक कमोबेश ऐसा ही होता भी आया था। भले ही यह अवधि 10 वर्ष नहीं हो लेकिन फिर भी यह एक उल्लेखनीय आंकड़ा होना चाहिए। चाहे जो भी हो बाहर से अर्थशास्त्री लाने का चलन समाप्त होना चाहिए। यह मौजूदा व्यवस्था करदाताओं के पैसे को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है।

सरकार की तरह आरबीआई भी ढेर सारे अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति करती है। सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार उनका प्रमुख होता है और आरबीआई में यह जवाबदेही अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षता करने वाले डिप्टी गवर्नर की होती है। वर्ष 2009 के बाद से देखा जाए तो केवल सुबीर गोकर्ण को ही पर्याप्त भारतीय अनुभव था। परंतु वह भी मौद्रिक या वित्त क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखते थे जबकि उनके काम के लिए यह आवश्यक था। वह मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अधिक उपयुक्त होते। इसके बाद ऊर्जित पटेल आए। उनकी विशेषज्ञता भी मौद्रिक अर्थशास्त्र में नहीं थी। हालांकि वह सन 1990 के दशक में आरबीआई में बतौर सलाहकार काम कर चुके थे। तमाम बौद्धिक क्षमता के बावजूद उन्हें आरबीआई में शोध विभाग के नेतृत्व का अवसर नहीं मिला। उनका स्थान विरल आचार्य ने लिया। मेरी दृष्टि में उनकी विशेषज्ञता भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के लिए ज्यादा थी। अब आरबीआई को उनका उत्तराधिकारी तलाशना है और मेरा सुझाव है कि उसे अपने शोध विभाग पर ही दृष्टि डालनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे 1996 में एसएस तारापोर की सेवानिवृत्ति तक वह करता आया है।

क्या किया जाना है? : मुझे लगता है कि सरकार को एक काडर तैयार करना चाहिए जो तेजी से काम करने में सक्षम हो। इस पैनल में 40 से 50 की उम्र के अर्थशास्त्रियों को स्थान मिलना चाहिए। आरबीआई के साथ-साथ आर्थिक सेवा के अर्थशास्त्रियों को इसके आवेदन की अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा किसी को इसमें शामिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर आईएएस, आईएफएस अधिकारियों को तो कतई नहीं। एक बार काडर तैयार होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार और डिप्टी गवर्नर का चयन इसमें से ही किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं तो आपकी उपयोगिता (जैसा कि एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में कहा भी) आर्थिक समीक्षा के संपादक से ज्यादा नहीं रह जाएगी। हालांकि उसके लिए भी अलग किस्म के कौशल की आवश्यकता होती है।

कानाफूसी

पुलिस की मुसीबत

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़ा जुर्माना लगाने की शुरुआत करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस खुद को अजीब परिस्थितियों में उलझा हुआ पा रही है। वहां ऐसी कई घटनाएं देखने में आ रही हैं जिनमें आम जनता ने पुलिस अधिकारियों या पुलिस कर्मियों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कई वीडियो तो ऐसे भी हैं जहां पुलिसकर्मी वसूली करते देखे जा सकते हैं। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह ने घोषणा की है कि जो पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर सामान्य से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। यातायात पुलिसकर्मियों से कहा गया है कि वे वाहन की जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें। यह भी कहा गया है कि उन्हें वाहनों को तभी रोकना चाहिए जब वाहन चालक कुछ गलती कर रहा हो।

विप्लव का दरबार

आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए भाजपा नेता और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव भी प्रदेश के सभी जिलों में जनता दरबार का आयोजन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों पश्चिम त्रिपुरा जिला अदालत के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने कहा कि वह समय की कमी के चलते अपने प्रदेश के लोगों से भलीभांति मिल नहीं पाते हैं लेकिन जब भी कोई उनके फेसबुक पेज के माध्यम से सहायता मांगता है, वह तत्काल उसकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही हर जिले में लोगों से प्रत्यक्ष संवाद कायम कर उनकी समस्याएं दूर करने का काम करेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में सत्ता में आने के बाद से ही देव अगरतला में जनता दरबार लगाते रहे हैं।

आपका पक्ष

हिंदी का उचित सम्मान जरूरी

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। 26 सितंबर, 1950 को भारतीय संविधान द्वारा इसे आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 (1) में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं इस पूरे पखवाड़े बल्कि पूरे माह में विशेषतः इसे याद करने के लिए सरकारी और स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालयों में कविता, निबंध, लेखन, भाषण प्रतियोगिता, विभिन्न स्लोगन, हिंदी गायन, आदि के माध्यम से हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। हिंदी सहज, सरल, देश की संपर्क भाषा है जो देश के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम साधन है। समूचे विश्व में हिंदी सीखने के प्रति ललक बढ़ रही है। कंप्यूटर में हिंदी सॉफ्टवेयर, अंग्रेजी शब्दकोष में हिंदी के शब्दों का समावेश, इंटरनेट पर धाक जमा रही हिंदी मोबाइल ऐप आदि हिंदी की ताकत और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। हिंदी डिजिटली समृद्ध, विश्वव्यापी, संस्कृति वाहक भाषा है जिसमें भरपूर अवसर समाहित है। हिंदी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता है। इन सबके बावजूद यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदी राजभाषा होने पर भी हमारे उच्चस्तर के शासकीय कार्यालयों, नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रभाव कम नहीं हो पा रहा है। यह एक गंभीर और सभी के लिए चिंतन का विषय है। इसके लिए जरूरी है कि बड़े अधिकारी, संभ्रात, उच्च वर्ग, राजनेता और सरकार की दोहरी नीति और मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। यह तय करना पड़ेगा कि हिंदी दिवस मात्र औपचारिकता बनकर नहीं रह जाए व हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जाए। हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस पर लोगों को जागरूक किया जाए।

मनोहरलाल उपाध्याय, इंदौर

मुरादाबाद के एक स्कूल में 14 सितंबर को बच्चों ने हिंदी दिवस मनाया *फोटो-पीटीआई*

जल्दबाजी में लागू हुए संशोधन

केंद्र सरकार ने यातायात को सुगम बनाने और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के लिए मोटर वाहन कानून में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों को 1 सितंबर से लागू किया गया है। इन नियमों को देर सबेर सभी राज्यों को लागू करना ही होगा। भले ही धारा 200 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके जुर्माने की रकम आधी कर दें। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा किए गए इन संशोधनों से देश की खराब यातायात व्यवस्था सुगम होगी और जनता नियमों का पालन करेगी। नियमों की सख्ती से पालन करने की आड़ में पुलिसकर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार करने की संभावना को देखते हुए इसके लिए भी एक स्पष्ट प्रावधान जरूरी है।

अनिल कोथुलकर, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।